रामजल सेतु लिंक परियोजना की डीपीआर का तकनीकी परीक्षण पूरा हुआ- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने परियोजना के वित्त पोषण के लिए पीआईबी नोट शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए

जयपुर, 1 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना की डीपीआर का तकनीकी परीक्षण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कर लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के वित्त पोषण के लिए पीआईबी नोट को शीघ्र अंतिम रूप देने और इसके लिए केन्द्र सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के विभिन्न घटकों में तेजी लाने और मिशन मोड पर काम करने के निर्देश भी दिए।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परियोजना के अंतर्गत बीसलपुर से मोर सागर (अजमेर), ईसरदा से बंध बारैठा (भरतपुर), ईसरदा से रामगढ़ (जयपुर), खुरा चैनपुरा से जयसमंद (अलवर) एवं ब्राह्मणी बैराज के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रामजल सेतु लिंक परियोजना के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिये।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रामजल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना) के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने परियोजना के पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी लेते हुए, शेष कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए। साथ ही, परियोजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने बीसलपुर से मोर सागर (अजमेर), ईसरदा से बंध बारैठा (भरतपुर), ईसरदा से रामगढ़ (जयपुर), खुरा चैनपुरा से जयसमंद (अलवर) एवं ब्राह्मणी बैराज के कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। शर्मा ने परियोजना के विभिन्न घटकों के अलाइनमेंट की जानकारी भी ली और परियोजना से संबंधित समस्त कार्यों का सघन पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रामगढ़ बैराज एवं महलपुर बैराज के काफर डेम एवं डेनेज फीडर का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने नवनेरा बैराज से मेज एनीकट के डूब क्षेत्र तक फीडर निर्माण एवं चम्बल एक्वाडक्ट के निर्माण कार्य, मेज एनीकट से गलवा बांध के डूब क्षेत्र तक फीडर ड्रेन, गलवा बांध से ईसरदा डूब क्षेत्र और बीसलपुर डूब क्षेत्र फीडर निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार सहित, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

निशिकांत दुबे ने बिना शर्त माफी मांगी

नई दिल्ली/भुवनेश्वर, 01 अप्रैल। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को नेहरू-गांधी परिवार के बारे में अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला गया और अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं बिना शर्त माफी चाहता हूं।

यह विवाद निशिकांत दुबे की 27 मार्च की टिप्पणी से उपजा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी धन और सीआईए एजेंटों के सहयोग से युद्ध लड़ा था, तथा ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने अमेरिकी सरकार, सीआईए और नेहरू के बीच कड़ी का काम किया था।

■ बीजू पटनायक पर टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सफाई दी और माफी मांगी।

इस दौरान, पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के अग्रणी नेताओं में शुमार बीजू पटनायक के संदर्भ में बोली गईं मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया।

यह मेरा व्यक्तिगत बयान है। नेहरू जी के ऊपर मेरे विचार को बीजू पटनायक के ऊपर समझा गया।

निशिकांत दुबे ने कहा बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा ऊंचे कद के नेता रहे हैं और रहेंगे।ß

मेरे वक्तव्य से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं।

'उपासना सैन्ट्रिक' बिल्डिंग के निर्माण में भारी लापरवाही, बिल्डर से जवाब तलब

हाईकोर्ट ने इस बिल्डिंग के निर्माण से परेशान अधिवक्ता हेमंग कुमावत द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे के आदेश दिये

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 1 अप्रेल। बिल्डरों द्वारा रिहायशी इलाकों में ऊंची इमारतें बनाते समय आसपास पड़ोस में रह रहे निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिस तरह अनदेखी की जाती है वह वर्तमान में गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। इसी मुद्दे को उठाते हुए अधिवक्ता हेमंग कुमावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल हेमंग टोंक रोड़ पर गांधी नगर मोड़ पर ए-1 कृष्णा नगर के निवासी हैं और उन्हीं के घर से संलग्न उपासना बिल्डर द्वारा "उपासना सैन्ट्रिक" नामक मल्टी स्टोरी का निर्माण किया जा रहा है। उनके द्वारा दायर याचिका में बताया गया कि जैसे-जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ती गई वैसे-वैसे ही उनके मकान में बिल्डिंग कन्स्ट्रशन का मलबा गिरने लगा। उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेडीए को कठोर आदेश दिये हैं कि 2 अप्रेल गुरुवार सुबह 11 बजे सर्वे किया जाये और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उसकी रिपोर्ट अगले 2-3 दिन में ही अदालत में पेश की जाये।

■ अधिवक्ता हेमंग कुमावत ने याचिका में बताया कि बिल्डिंग निर्माण के दौरान उसके घर पर मलबा गिर रहा है, जिससे उसके घर को नुकसान हुआ है।

■ अदालत ने जेडीए को भी फटकारा क्योंकि उसके आदेश के बावजूद उक्त क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिल्डर द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्या कदम उठाये गये।

■ अदालत ने अगले 2-3 दिन में ही सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये।

याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने कई बार बिल्डर व कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करा ताकि किसी दिन गंभीर मामला ना हो जाये। परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने याचिका में बताया कि 18 फरवरी 2026 को एक बिल्डिंग की छत से भारी भरकम मलबा उनके मकान पर गिरा जिससे घर में नुकसान हुआ और घर की खिड़कियां भी टूट गई। उन्होंने इस वारदात की शिकायत और उनके घर में हुई क्षति के बारे में ज्योति नगर थाना में सूचना दी और जेडीए में भी इसकी शिकायत दर्ज की थी। जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए बिल्डर ने अपनी भूल मानी और क्षमा भी मांगी। परंतु इसके बावजूद बिना किसी सुरक्षा के बिल्डिंग का कार्य निरंतर चलता जा रहा है और आये दिन अधिवक्ता हेमंग कुमावत के मकान पर मलबा गिर रहा है।

इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गणेश मीणा ने 16 मार्च को जेडीए व उपासना ग्रुप और ग्लोबल कंन्स्ट्रशन को भी नोटिस जारी करे थे। और कहा था कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां बिना सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण कार्य कर रही हैं जिससे याचिकाकर्ता के मकान को नुकसान हो रहा है। उन्होंने जेडीए को आदेश दिये थे कि वह मौका मुआयना करे और यह सुनिश्चित करे कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी निर्माण कंपनियों द्वारा। न्यायाधीश गणेश मीणा ने सर्वे की रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख तक कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे। हैरानी की बात है कि जेडीए ने कोर्ट के आदेश अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश समीर जैन ने जेडीए के खिलाफ कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि गुरुवार सुबह 11 बजे सर्वे किया जाये और उसकी रिपोर्ट अगले 2-3 दिन में ही अदालत में पेश की जाये।

अमरावती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बिल में उन किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए समय-सीमा तय होनी चाहिए थी, जिन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने के लिए अपनी ज़मीनें दी थी।

प.बंगाल, तमिलनाडु, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस और माकपा झूठे, मनगढ़ंत और भ्रामक दावे कर रहे हैं। ये संशोधन किसी धर्म या संगठन के खिलाफ नहीं हैं। चुनावों को देखते हुए विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है।

इस समय चल रहे खाड़ी संघर्ष और आगामी राज्य चुनावों के अभियान के बीच, सरकार ने 25 मार्च को चुपचाप एफसीआरए संशोधन विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के तहत, केन्द्र सरकार को हजारों संगठनों की विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियों, जैसे स्कूल, अस्पताल और पूजा स्थल, पर व्यापक अधिकार मिल जाते। खासकर केरल में विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। वाम दलों और कांग्रेस दोनों ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक संगठनों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि यह कानून आरएसएस को लाभ पहुंचाएगा। राज्य सरकारें भी चिंतित हैं, क्योंकि यदि यह कानून लागू होता है तो एफसीआरए से जुड़ी सभी जांचों पर केन्द्र को वीटो पावर मिल जाएगी, जिससे राज्यों की भूमिका पूरी तरह दरकिनार हो जाएगी। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि यह विधेयक पारित हुआ, तो केन्द्र गैर-भाजपा शासित राज्यों में धार्मिक और अल्पसंख्यक संस्थानों की संपत्तियां जब्त कर सकता है। गौरतलब है कि इन संशोधनों में स्वतंत्र अपीलीय निकाय का भी प्रावधान नहीं है, और सभी फैसले कार्यपालिका द्वारा नियुक्त अधिकारी के हाथ में होंगे।

सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावित बदलाव "डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी" का गठन है, जिसे किसी संगठन का पंजीकरण रद्द होने, समर्पित (सरेन्डर) होने या समाप्त होने पर विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर नियंत्रण लेने का अधिकार होगा।

चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय पर बम धमाका

खालिस्तानी आतंकी सुखजिंदर सिंह सोशल मीडिया पोस्ट में इस हमले की जिम्मेवारी ली

चंडीगढ़ , 01 अप्रैल। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर बुधवार की शाम हुए बम धमाके की जिम्मेदारी एक खालिस्तानी आतंकी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली है। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एनआईए तथा सेना के अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 37 स्थित भाजपा कार्यालय की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा यूटी चंडीगढ़ , पंजाब के मोहाली तथा हरियाणा के पंचकूला की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

■ पुलिस को घटना का एक सीसी टीवी फुटेज मिला है जिसमें एक युवक ग्रेनेड से पिन निकालते हुए और ग्रेनेड फेंक कर भागते हुए दिख रहा है।

बुधवार की शाम पांच बजे के करीब सेक्टर-37 स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय के बाहर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के कारण पार्किंग में खड़े कई वाहन तथा इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए। घटना की सूचना मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस की कई टीमें जांच के लिए मौके पर पहुंची। इसी दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से एक वीडियो मिला है। जिसमें एक युवक ग्रेनेड का पिन निकालकर फैंकते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह पंजाबी में गालियां देते हुए भाग जाता है। हमलावरों की संख्या दो होने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस जांच अभी चल रही ही रही थी कि खालिस्तानी आतंकी सुखजिंदर सिंह बब्बर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने इस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के लिए साइबर सैल को निर्देश जारी कर दिए हैं। आतंकी की तरफ से लिखा गया है कि सुखजिंदर सिंह बब्बर 1 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ सेक्टर-37 में हुए ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी लेता है। हम भारतीय सिस्टम को बताना चाहते हैं कि उसके पास पंजाब के सिख युवाओं को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है।

इस बीच चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सैल, सीएफएसएल की टीमों तथा एनआईए की टीमों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, सेना के अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं।

कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक

कुवैत सिटी, 01 अप्रैल। कुवैत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बुधवार को बताया कि कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया। इससे फ्यूल स्टोरेज टैंकों में भीषण आग लग गई। इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

गल्फ न्यूज के दुबई कार्यालय से साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार, सिविल एविएशन अथॉरिटी के आधिकारिक प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजही ने कहा कि यह हमला ईरान और उसके समर्थक सशस्त्र समूहों ने किया। उन्होंने इसे हवाई अड्डे पर "खुला हमला" बताया। उन्होंने बताया कि ड्रोन ने कुवैत एविएशन फ्यूल कंपनी के फ्यूल टैंकों को निशाना बनाया। इससे उस जगह पर भीषण आग लग गई। हालात को नियंत्रण में करने के लिए तुरंत आपातकाल बलों को भेजा गया। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि नुकसान सिर्फ सामान का ही हुआ है।

प्र.मंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की विशेष बैठक बुलाई

नई दिल्ली, 01 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की एक विशेष बैठक की, जिसमें पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। यह इस मुद्दे पर दूसरी विशेष बैठक थी।

■ बैठक में पश्चिम एशिया संकट के दौरान देश में एलपीजी पैट्रोल-डीज़ल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई

प्रधानमंत्री ने आम लोगों की जरूरतों की उपलब्धता की समीक्षा की और कहा कि इस वैश्विक संकट का असर नागरिकों पर न पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि अफवाहों को रोका जा सके। अंत में, प्रधानमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे इस स्थिति से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर एलपीजी और एलएनजी, की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। एलपीजी और एलएनजी अब अलग-अलग देशों से मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी के दाम अभी स्थिर हैं और कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए नियमित कार्रवाई की जा रही है।

पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। गर्मियों में बिजली की कमी न हो, इसके लिए गैस आधारित बिजली संयंत्रों को कुछ छूट दी गई है और थर्मल पावर स्टेशनों तक ज्यादा कोयला पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

कृषि, नागरिक उड्डयन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे अन्य क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई। खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यूरिया उत्पादन जारी रखा जा रहा है और डीएपी/एनपीके खाद के लिए विदेशों से समन्वय किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से नजर रखें। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, मनोहर लाल खट्टर, प्रल्हाद जोशी, के राममोहन नायडू और हरदीप सिंह पुरी समेत कई मंत्री शामिल हुए। इनके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास तथा कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन भी बैठक में मौजूद थे।

सहायक निदेशक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सचिव नरेश गोकलानी ने सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) विकास जैफ को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

इस नोटिस में विकास जैफ से तीन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि, क्या बायोफ्यूल प्राधिकरण में पदस्थापन के लिए विकास जैफ ने कोई आवेदन किया था? यदि आवेदन किया था तो कब और किस माध्यम से अथवा सीधे ही बायोफ्यूल प्राधिकरण में आवेदन किया था? क्या उन्होंने आवेदन से पूर्व कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग से इस संबंध में प्रशासनिक अनुमति प्राप्त की थी?

इन तीनों बिंदुओं पर विकास जैफ को 7 दिन में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं, इसके बाद ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में निर्णय होगा।

छह वर्ष की बालिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह किराए के मकान में रहकर रेस्तरां में काम करता है, जहां अभियुक्त भी उसके साथ काम करता है। सुबह वह अपने दोनों बच्चों को लेकर रेस्तरां पर काम करने आया था। दोपहर के समय अभियुक्त उसकी साढ़े छह साल की बेटी को उसके किराए के मकान की ओर ले गया था। जब काफी देर तक बेटी नहीं लौटी, तो उसने उसे आसपास तलाशा, लेकिन उसका पता नहीं चला। इस पर उसने अभियुक्त से सख्ती से पूछताछ की। इस दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर लाश को प्लास्टिक के कट्टे में रखकर छत पर छोड़ आया। जब उसने छत पर जाकर देखा तो कट्टे में उसकी बेटी की लाश मिली। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

लिएंडर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की। खेल और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका जुनून सचमुच सराहनीय है। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिएंडर पेस ने भी 'एक्स' पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व, ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति उनके जुनून से अभिभूत हूं। आपकी टीम का हिस्सा बनकर और आपके मार्गदर्शन में देश की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। जय हिंद, जय भारत।

बुरी तरह निराश, "घायल" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था। ट्रंप ने गलती से वेनेज़ुएला को बाकी दुनिया के लिए एक मॉडल मान लिया था।

दूसरी ओर, ईरान भी उतना ही मुखर है कि वह युद्धविराम नहीं करेगा और लड़ाई जारी रखेगा। ईरान यह भी कह रहा है कि उसके नेता सुरक्षित हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं।

यदि कुछ हुआ, तो ईरान को उसकी मौजूदा स्थिति में छोड़ देना सबसे खराब परिणाम होगा। पूरा पश्चिम एशिया, यानी सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और अन्य सभी, ईरान के रहमो- करम पर होंगे। युद्ध के दौरान वे पहले ही आतंकित हो चुके हैं, और अधिक शक्तिशाली हुआ ईरान उन्हें और भ्रमित करेगा।

एकमात्र पक्ष, जो न तो जीत का दावा कर रहा है और न युद्ध के अंत की बात कर रहा है, वह इज़रायल है, जिसने ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार हमले किए हैं और लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान तेज किया है। यदि अमेरिका अचानक इस पूरे मामले से हाथ खींच लेता है, तो इज़रायल असुरक्षित हो जाएगा।

इज़रायल की अजेय होने की छवि बुरी तरह टूट चुकी है। उसे न तो ईरान पर और न हिज़्बुल्लाह पर ही कोई स्पष्ट जीत मिली है। बल्कि, हिज़्बुल्लाह और अधिक आक्रामक हो सकता है।

इसलिए, युद्ध के परस्पर विरोधी दावे दुनिया को वहीं छोड़ देते हैं, जहाँ वह पहले थी, बल्कि शायद उससे भी बदतर स्थिति में।

यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह ठहराव और अव्यवस्था की स्थिति है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और दुनिया भर के देश तेल और गैस की आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय कर रहे हैं। इसका आर्थिक प्रभाव कम विकसित और गरीब देशों पर और भी गंभीर होगा। अफ्रीकी देश पहले से ही इसके प्रभाव की शिकायत कर रहे हैं।

लेकिन सबसे बड़ा नुकसान संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है। एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में उसकी छवि को धक्का लगा है। अमेरिका के अनिश्चित व्यवहार ने कहीं और नहीं, बल्कि वहीं शासन परिवर्तन की आवश्यकता पर सवाल खडे कर दिए हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के लिए यह कितनी शर्मनाक वापसी है।

इस युद्ध में अमेरिका को जो गंभीर झटके लगे हैं, उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। इसी सप्ताह, अमेरिका के दो अत्यंत महत्वपूर्ण निगरानी विमान-ई3 सैंट्री पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। ऐसे विमान बहुत अधिक संख्या में नहीं होते और इन्हें आसानी से बदला भी नहीं जा सकता।

पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकाने बुरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। अब यह सवाल उठेगा कि क्या इन्हें फिर से बनाया जाएगा या अमेरिका को इन्हें समेटने के लिए कहा जाएगा। आखिरकार, इन ठिकानों ने उन देशों को कोई सुरक्षा नहीं दी, जिन्होंने इन्हें अपने यहाँ स्थापित होने दिया था। उल्टा, ये ठिकाने हमलों का लक्ष्य बन गए।

अचानक वापसी के नुकसान को देखते हुए, कभी-कभी ऐसा लगता है कि ट्रंप यह सब ईरानियों को ढीला करने के लिए एक चाल के रूप में कर रहे हैं। वे यह भी कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर वे भविष्य में वापस आएंगे।

लेकिन ट्रंप के आसपास सब कुछ एक अजीब नाटक जैसा लगता है। कोई भी स्पष्ट रुप से यह नहीं कह सकता कि उनका असली मतलब क्या है। दुनिया मानो पागलपन की ओर बढ़ रही है।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में शामिल करने का निर्देश दिया, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 13 नवंबर 2025 के अंतरिम आदेश से एकलपीठ के इस आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ के इस आदेश को प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गत 9 जनवरी के आदेश से हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह 31 मार्च से पहले प्रार्थियों का मामला तय करे। वहीं प्रार्थियों के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए भी कहा।

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में खंडपीठ ने उनकी अपीलों पर सभी पक्षकारों की बहस सुनकर 19 जनवरी 2026 को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मामले से जुडी अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा आयोजक एजेंसी ने आगामी 5 और 6 अप्रैल को परीक्षा तिथि घोषित कर दी है।

यदि भर्ती परीक्षा हो जाती है तो प्रार्थी सहित अन्य अभ्यर्थियों के अधिकार इस नई भर्ती में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसलिए भर्ती परीक्षा को 4 सप्ताह के लिए स्थगित किया जाए।

2019 के बाद, पहली बार, ईरान का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रमुख निर्यात केन्द्र खार्ग द्वीप से अपना कार्गो लोड किया, होर्मुज़ स्ट्रेट पार कर चुका है और 4 अप्रैल को भारत पहुंचने की उम्मीद है। यह गुजरात के वडीनार बंदरगाह पर लगभग 6 लाख बैरल कच्चा तेल उतारेगा। मई 2019 के बाद यह पहली ऐसी खेप है, जो ऐसे समय पर आ रही है, जब भारतीय रिफाइनरियों के भंडार घट रहे हैं।

ईरान पर प्रतिबंध दोबारा तब लगाए गए थे जब अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान डॉनल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा द्वारा किए गए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था, यह कहते हुए कि यह समझौता तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने में विफल रहा। यह खेप अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों में अस्थायी ढील दिए जाने के बाद आई है, जबकि वह वैश्विक तेल कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।

मंगलवार को ब्रेंट क्रूड 118.35 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जो हालिया संघर्ष शुरू होने के बाद के उच्चतम स्तर के करीब है। होर्मुज़ स्ट्रेट से आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं के बीच व्यापारी तेजी से सौदे कर रहे हैं। मार्च में तेल की कीमतों में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दशकों में सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है।

अमेरिका ने 20 मार्च से समुद्र में लदे और रुके हुए ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति दी है, जो 19 अप्रैल तक लागू सीमित छूट है।

इस अवधि में भारत के साथ चीन के भी प्रमुख खरीदार बनने की उम्मीद है, जो प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल खरीदता रहा है।

यह खेप एक अन्य ईरानी ऊर्जा आपूर्ति के तुरंत बाद आई है। इस सप्ताह की शुरुआत में "सी बर्ड" नामक टैंकर मैंगलोर बंदरगाह पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर पहुंचा, जिससे घरेलू कमी से जूझ रहे भारत को कुछ राहत मिली।

सैन्य अनिश्चितता भी बाजार में अस्थिरता बढ़ा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, "मुद्दा अप्रत्याशित बने रहना है।" और यह भी कहा कि युद्ध चार, छह, आठ सप्ताह या उससे अधिक समय तक चल सकता है। 2019 में ईरान से तेल आयात रोकने के बाद, भारत अपने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाया, जिसमें इराक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा, और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भी आपूर्ति बढ़ाई। वर्ष 2023 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, रूस तेल का एक प्रमुख स्रोत्र बन गया।

भारत की ऊर्जा मांग बहुत अधिक है। देश में प्रतिदिन 5.6 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है, जिससे वह अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

इस मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियां सक्रिय रूप से आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं, जिसमें अप्रैल के लिए रूस से लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन खरीद के सौदे शामिल हैं, जो पिछले वर्ष से थोड़ा ही कम है।

हालांकि, इन बैरल्स के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देश भी सस्ते रूसी तेल की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उपलब्धता घट रही है और भारत को अपने स्रोत बढ़ाने के प्रयास तेज करने पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ईरान भविष्य में भारतीय टैंकरों को नियमित रूप से सुरक्षित जलमार्ग देगा या नहीं। फिर भी कुछ गतिविधियां जारी हैं। दो भारतीय टैंकर होर्मुज़ स्ट्रेट पार कर चुके हैं और भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिति और जटिल होती जा रही है। "ब्लूमबर्ग" की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने पाकिस्तान के लगभग 20 जहाजों को प्रति सप्ताह होर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दी है। हालांकि पाकिस्तान के जहाज खाड़ी में फंसे हुए नहीं हैं और वह उर्वरक जैसे आवश्यक सामान के परिवहन के लिए अन्य विकल्प तलाश रहा है।

भारत की आवश्यकता कहीं अधिक है। देश हर साल 1.7 से 1.8 अरब बैरल कच्चा तेल आयात करता है, जो लगभग 900 बहुत बड़े तेल टैंकर के बराबर है, यानी लगभग 75 खेप प्रति माह। तुलना में पाकिस्तान को केवल दो वीएलसीसी प्रति माह की आवश्यकता होती है।

ईरानी कच्चे तेल की इस खेप के आगमन से उम्मीदें जगी हैं कि आगे और आपूर्ति हो सकती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह व्यापार के स्थायी रूप से फिर से शुरू होने का संकेत है या केवल एक अस्थायी अवसर।

इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने मंगलवार देर रात यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष से कहा कि तेहरान के पास युद्ध समाप्त करने की "आवश्यक इच्छाशक्ति" है, लेकिन इसके लिए "जरूरी शर्तों की गारंटी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न आए।"

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600